**Creation of an All India Education Service**

1439. SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) what is the progress made so far in the matter of creation of an All India Education Service;

(b) which are the States that have opted for this Service; and

(c) what is the objection if any, thereto of the other States?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EDUCATION AND CULTURE (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) to (c) The National Policy on Education—1986 has laid down:—"A proper management structure in education will entail the establishment of the Indian Education Service as an All-India Service. It will bring a national perspective to this vital sector. The basic principles, functions and procedures of recruitment to this service will be decided in consultation with the State Governments".

The details are being worked out.

**महारानी लक्ष्मी बाई के किले का अधिग्रहण किया जाना**

1440. **डा० गोविन्द दास रिछारिया :** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने रक्षा मंत्रालय से वीरांगना महारानी लक्ष्मी बाई के किले का अधिग्रहण कर लिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं और किले का अधिग्रहण कब तक कर लिए जाने की सभावना है ; और

(ग) किले को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में सुरक्षित रखने के लिए सरकार क्या-क्या कदम उठाने का विचार रखत है ?

**शिक्षा और संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) :** (क) जी, हां ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) झांसी स्थित किले को राष्ट्रीय महत्व के एक स्मारक के रूप में घोषित किए जाने के लिए कदम उठाने के अतिरिक्त इसके संरक्षण और भू-दृश्य निर्माण का एक चरणबद्ध कार्यक्रम शुरू किए जाने का प्रस्ताव है ।

**नई शिक्षा नीति क्रियान्वित करने के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता**

1441. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार जैसे पिछड़े राज्यों में नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए केन्द्र द्वारा कितनी और किस प्रकार की सहायता देने का प्रस्ताव है ; और

(ख) इस नई शिक्षा नीति द्वारा निरक्षरता की दर किस सीमा तक कम होने की संभावना है ?

**शिक्षा और संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) :** (क) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के अन्तर्गत किसी अन्य राज्य की तरह, बिहार को भी दी जाने वाली वित्तीय सहायता अलग-अलग योजनाओं पर निर्भर होगी । राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय कार्यवाही योजना तैयार कर रहा है । कार्यवाही योजना के यथा अनुमोदन के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में योजनाएं यथासमय विकसित की जायेंगी ।

(ख) निरक्षरता उन्मूलन कार्यक्रमों में सभी आयु वर्ग के निरक्षरों को शामिल किये जाने की परिकल्पना की गयी है । देश में साक्षरता दर का पता 1991 में तब चलेगा जब जनगणना आयोजित की जायेगी । अगली दो पंच वर्षीय योजनाओं की